



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2009/कार्तिक 22, 1931

No. 657]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2009/KARTIKA 22, 1931

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 823(अ).—चूँकि, वायुयान नियम, 1937 में संशोधन करने के प्रस्ताव का गारूप, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 21 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 539(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए इसकी प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करायी गईं।

और चूँकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां दिनांक 21 जुलाई, 2009 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थीं।

और चूँकि ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त हुए थे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए वायुयान नियमावली, 1937 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः :—

1. (1) इन नियमों को वायुयान (खतरनाक माल का वहन) संशोधन नियम, 2009 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2003 में,—

(1) नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“12. प्रशिक्षण की अपेक्षाएं.—(1) कोई भी व्यक्ति खतरनाक माल के परिवहन में किसी भी रीति में स्वयं को तब तक नहीं लगाएगा जब तक कि उसने अपने उत्तरदायित्वों के अनुरूप उचित प्रशिक्षण न लिया हो।

(2) ऐसा प्रशिक्षण किसी व्यक्ति के उस पद पर नियोजन के समय प्रदान किया जाएगा या सत्यापित किया जाएगा जिसमें खतरनाक माल का परिवहन में अंतर्विलित हो और प्रत्यावर्ती प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण के चौबीस मास के भीतर होगा।

12क. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना और अनुमोदन.—

(1) प्रारंभिक और प्रत्यावर्ती खतरनाक माल प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित द्वारा या उनकी ओर से स्थापित किए और चलाए जाएंगे,—

- (क) खतरनाक माल को भेजने वाले, जिनमें पैकर्स और माल भेजने वाले की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति या संगठन भी हैं;
- (ख) प्रचालक;
- (ग) भूमि हथालन, अभिकरण जो प्रचालक की ओर से स्थौरा की स्वीकृति, संभलाई, लदाई, उतराई, अंतरण या अन्य प्रक्रियाएं करते हैं;
- (घ) किसी विमानपत्तन पर अवस्थित ऐसे भूमि हथालन, अभिकरण जो प्रचालक की ओर से यात्री संबंधी कार्यवाहियां करते हैं;
- (ङ) ऐसे अभिकरण, जो किसी विमानपत्तन में अवस्थित नहीं हैं, जो प्रचालक की ओर से यात्रियों की जाँच-पड़ताल करने संबंधी कार्य करते हैं;

- (च) दुलाई अप्रेषित करने वाले; और
(छ) यात्रियों और उनके सामान और स्थोरा की सुरक्षा जाँच में लगे अधिकरण ।

(2) प्रशिक्षण, प्रशिक्षित किए जाने वाले कार्मिकों के उत्तरदायित्वों की अपेक्षानुरूप प्रदान किया जाएगा और ऐसे प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

- (क) साधारण उपबंधों से सुपरिचित कराने के उद्देश्य से साधारण सुपरिचय प्रशिक्षण;
(ख) विनिर्दिष्ट कृत्य संबंधी प्रशिक्षण जिसमें उस कृत्य के संबंध में, जिसके लिए वह व्यक्ति उत्तरदायी हैं, लागू अपेक्षाओं में विस्तृत प्रशिक्षण देना भी है;
(ग) सुरक्षा प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत खतरनाक माल द्वारा प्रस्तुत परिसंकट, सुरक्षित हथालन और आपातकाल में कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी है ।

(3) किसी भारतीय प्रचालक द्वारा या उसकी ओर से या भारत में किसी अन्य अधिकरण द्वारा स्थापित और चलाया जा रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम महानिदेशक द्वारा पुनर्विलोकन और अनुमोदन के अध्वधीन होगा ।

(4) किसी विदेशी प्रचालक द्वारा या उसकी ओर से कर्मचारियों के लिए स्थापित और चलाया जा रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम महानिदेशक द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही विधिमान्य रूप में स्वीकार किया जाएगा कि उसे प्रचालक के देश के विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।

(5) उप-नियम (3) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने हेतु आवेदन महानिदेशक को, ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों या दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(6) महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपना समाधान होने पर, किसी संगठन को प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित या उसे चलाने का अनुमोदन प्रदान कर सकेगा ।

(7) उप-नियम (6) के अधीन दिया गया अनुमोदन, जब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाता, तब तक वह एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा जिसे एक बार में एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ।

(8) अनुमोदन प्रदान करने के लिए पचास हजार रुपए की फीस संदेय होगी और उसके नवीकरण के लिए पच्चीस हजार रुपए फीस संदेय होगी ।

(9) फीस का संदाय चेतन और लेखा कार्यालय, महानिदेशक नागर विमानन, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा ।” ;

(2) नियम 15 में “महानिदेशक” शब्द के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी” ।

[फा. सं. एवी-11012/14/09-ए]

प्रशान्त सुकुल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206(अ), तारीख 5 मार्च, 2003 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 795(अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2003, सा.का.नि. 796(अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2003, सा.का.नि. 600(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2006 और सा.का.नि. 231(अ), तारीख 19 मार्च, 2007 द्वारा उनका पश्चात्पूर्ति संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2009

G.S.R. 823(E).—Whereas, the draft of proposal to amend the Aircraft (Amendment) Rules, 1937 was published by the Ministry of Civil Aviation vide notification number G.S.R. 539(E), dated 21st July, 2009, as required by Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 21st July, 2009;

And whereas the objections or suggestions received in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:—

1.(1) These rules may be called the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods), Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003,—

(1) for rule 12, the following rules shall be substituted, namely:—

“12. Requirement of Training.—(1) No person shall engage himself in any manner in the transport of dangerous goods unless he has undergone proper training commensurate with his responsibilities.

(2) The training shall be provided or verified upon the employment of a person in a position involving the transport of dangerous goods and recurrent

training shall take place within twenty-four months of the previous training.

12A. Establishment and Approval of Training Programme.—(1) Initial and recurrent dangerous goods training programmes shall be established and maintained by or on behalf of,—

- (a) shippers of dangerous goods including packers and persons or organisations undertaking the responsibilities of the shipper;
- (b) operators;
- (c) ground handling agencies which perform, on behalf of the operator, the act of accepting handling, loading, unloading, transferring or other processing of cargo;
- (d) ground handling agencies located at an airport which perform, on behalf of the operator, the act of processing passengers;
- (e) agencies, not located at an airport, which perform on behalf of the operator, the act of checking in passengers;
- (f) freight forwarders; and
- (g) agencies engaged in the security screening of passengers and their baggage and cargo.

(2) Training shall be provided in the requirements commensurate with the responsibilities of the personnel being trained and such training shall include,—

- (a) general familiarisation training aimed at providing familiarity with the general provisions;
- (b) function-specific training providing detailed training in the requirements applicable to the function for which that person is responsible; and
- (c) safety training covering the hazards presented by dangerous goods, safe handling and emergency response procedure.

(3) A training programme established and maintained by or on behalf of an Indian operator or by any other agency

in India shall be subjected to review and approval by the Director-General.

(4) The training programme established and maintained by or on behalf of a foreign operator for their own staff shall be accepted as valid by the Director-General on production of evidence that it has been approved by the regulatory authority of the State of the Operator.

(5) An application for grant of approval under sub-rule (3) shall be made to the Director-General in such form and contain such particulars or documents as may be specified by him.

(6) The Director-General or any other officer authorised in this behalf by the Central Government may, on being satisfied, grant approval to an organisation to establish or maintain the training programme.

(7) Unless suspended or cancelled, the approval granted under sub-rule (6) shall remain valid for a period not exceeding one year, which may be renewed for a period not exceeding one year at a time.

(8) A fee of rupees fifty thousand shall be payable for the grant of approval and rupees twenty-five thousand shall be payable for renewal thereof.

(9) The fee shall be paid by crossed Indian Postal Order or Demand Draft drawn in favour of Pay and Accounts Office, Director General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation, New Delhi.”;

(2) in rule 15, for the words “the Director-General”, the following words shall be substituted, namely :—

“the Director-General or any officer authorised in this behalf by the Central Government”.

[F. No. AV-11012/14/09-A]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number G.S.R. 206(E), dated the 5th March, 2003 and was subsequently amended *vide* number G.S.R. 795(E) dated the 6th October, 2003, G.S.R. 796(E), dated the 6th October, 2003, G.S.R. 600(E), dated the 27th September, 2006 and G.S.R. 231(E), dated the 19th March, 2007.